

# डेयरी के निवेश प्रस्ताव से 60 हजार को मिलेगा रोजगार

## बुंदेलखंड और पूर्वांचल में तेजी से बढ़ रहा है डेयरी कारोबार

अमर उजाला ब्यूरो

### पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर फोकस

लखनऊ। प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी डेयरी कारोबार तेजी से विस्तार पा रहा है। हाल ही में दो दिनों के भीतर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि इससे पहले 25 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से अधिकांश निवेश पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों से जुड़े हैं।

डेयरी नीति लागू होने के बाद

सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में डेयरी परियोजनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। बुंदेलखंड पैकेज के तहत विशेष निवेश किया जा रहा है। बांदा में 20 हजार लीटर क्षमता वाला नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय दोनों बढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुध संग्रह केंद्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि डेयरी को खेती के विकल्प के रूप में स्थिर आय का स्रोत बनाया जा सके। पूर्वांचल में महिला डेयरी समितियों के जरिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया गया है। गाजीपुर, जौनपुर और बलिया में संचालित मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना है, जिसमें चिलिंग प्लांट और संग्रह केंद्रों का विस्तार शामिल है।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। राजधानी में आयोजित दुग्धशाला विकास विभाग के स्थापना दिवस समारोह के दौरान

इन नए प्रस्तावों को गति मिली। पहले ही 796 प्रस्तावों पर एमओयू हो चुका है, जिससे लगभग 60 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

### सरकार दे रही 50 फीसदी तक अनुदान

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रति

यूनिट 80 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध है। इसके अलावा नई डेयरी इकाइयों और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए मशीनरी व तकनीक पर 10 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

### नंद बाबा दुग्ध मिशन का असर

इस मिशन के तहत अब तक 10 हजार से अधिक

लाभार्थियों को 84 करोड़ रुपये की सहायता सीधे खातों में दी गई है। साथ ही 4000 से अधिक दुग्ध सहकारी

समितियों का गठन कर करीब 1.5 लाख दुग्ध उत्पादकों को इससे जोड़ा गया है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।

